epaper
हिन्दुस्तान

निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ते हम

25/04/2022

कोविड-19 और यूक्रेन संकट की चुनौतियों के बीच पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पाद निर्यात 419.65 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 249.24 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का उत्पाद निर्यात 292 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 206 अरब डॉलर था। यह कोई छोटी बात नहीं है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वर्ष 2021-22 में भारत से करीब 75 लाख टन गेहूं निर्यात के बाद अब हमारा देश दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकों में उभरता दिख रहा है।

इस समय भारत का तेजी से बढ़ता निर्यात ग्राफ इस बात का प्रतीक है कि भारतीय उत्पादों की मांग दुनियाभर में बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात की ऊंचाई के संकेत लगातार उभर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा उत्पाद निर्यात अमेरिका को किया गया। संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड को भी बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए। आयातक देशों ने कोविड-19 के बीच पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चमड़ा, कॉफी, प्लास्टिक, रेडीमेड कपड़े, मांस व दुग्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद, तंबाकू आदि खूब आयात किए। अब भारत अधिक मूल्यवर्द्धित और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है।

वित्त वर्ष 2021-22 में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश, नीदरलैंड जैसे देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए।

यहां स्कैन करें

जयंतीलाल भंडारी | अर्थशास्त्री

निर्यात में इस तेजी से कई कारण हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विनिर्माण क्षेत्र को लॉकडाउन से बाहर रखने के कारण उत्पादन में गतिरोध नहीं आया। देश के आईटी विशेषज्ञ देश के कोने-कोने से आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर निर्यात की कमाई को ऊंचाई पर पहुंचाते रहे। देश में कॉरपोरेट कर की दर घटाई गई। एमएसएमई की परिभाषा को सुधारा गया, ताकि कई मध्यम आकार की इकाइयों को भी इसका लाभ मिले। ढांचागत व्यवस्था में किए गए सुधार से भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ने में मदद मिली और भारत में सामान बनाने वाले निर्यातकों को सस्ते श्रम की तलाश में देश के दूरदराज तक पहुंचने में सरलता हुई। दुनियाभर में तेजी से बदलती यह धारणा भी लाभप्रद रही है कि भारत उत्पाद निर्यात के लिहाज से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कोविड-19 के कारण चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के बीच भारत ने कोरोना से लड़ाई में सबके प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाई। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत ने वैश्विक व्यापार व निर्यात के नए मौके भी मुट्ठियों में किए। हालांकि, वर्ष 2021-22 में निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद देश को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें कई बातों पर ध्यान भी देना होगा। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। देश में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से दक्ष बनाना होगा। निर्यात के लिए बाजार ढूंढ़ने होंगे। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने होंगे। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पर खास ध्यान देना होगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट के तहत सेज की नई अवधारणा और सेज को उपयोगी बनाने हेतु इसके नियमों में आमूलचूल परिवर्तन से अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जा सकेगा। इससे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और देश से तेजी से निर्यात बढ़ाने की डगर सरल हो जाएगी। साथ ही, प्रभावी निर्यात प्रोत्साहनों से भारत दुनिया का प्रमुख निर्यातक देश और विभिन्न वैश्विक औद्योगिक जरूरतों की आपूर्ति करने वाले मददगार देश के रूप में दिखाई दे सकेगा। चूंकि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान करीब 45 फीसदी है और इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ने की नई संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए ग्लोबल मार्केट इंटेलीजेंस नेटवर्क की स्थापना से लाभ मिलेगा।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की उस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को साकार किया जा सकेगा, जिसमें कहा गया है कि बड़े बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अंतिम रूप देने, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और छूट योजना के विस्तार, वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2030 तक 1,000 अरब डॉलर के उत्पाद के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचने की जो प्रबल संभावना जताई गई है, उसके मद्देनजर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति अहम होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)